

माननीय न्यायमूर्ति एन.के. सोढ़ी और एन.के. सूद के समक्ष

दया शंकर - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

सी.पी.डब्ल्यू. 2002 का 7143

22 अप्रैल, 2003

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद, 226-हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994-एस.11(8)-हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994-आर.1.71(6)-निगम के मेयर के पद के लिए चुनाव-पद आरक्षित पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए - उम्मीदवार 'गोस्वामी' जाति का है - हरियाणा राज्य गोस्वामी जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं कर रहा है - मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है - केवल इसलिए कि यूपी. जिस राज्य से उम्मीदवार ने प्रवास किया था, उसने गोस्वामी को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया था, वह पिछड़े वर्ग को दिए जाने वाले लाभों का दावा नहीं कर सकती है, जब गोस्वामी जाति को हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है - चुनाव याचिका दायर करने के उपाय का सहारा लिए बिना चुनाव को चुनौती - का अस्तित्व ऐसा उपाय कला के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। 226 - निगम के मेयर के रूप में प्रतिवादी के चुनाव को रद्द करते हुए याचिका स्वीकार की गई।

माना गया कि प्रतिवादी संख्या 6 'गोस्वामी' जाति से संबंधित है जिसे हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है। किसी भी उत्तरदाता द्वारा ऐसी कोई घोषणा/अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। उत्तरदाताओं 2 और 6 द्वारा प्रस्तुत एक प्रमाण पत्र तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा जारी किया गया है और भले ही याचिकाकर्ता यूपी राज्य में पिछड़ा वर्ग है। उसे हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता क्योंकि हरियाणा राज्य ने 'गोस्वामी' जाति को पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया है। याचिकाकर्ता मूल रूप से यूपी राज्य का है। लेकिन अब वह फरीदाबाद में बस गई हैं जहां से उन्होंने निगम का चुनाव लड़ा। जब एक राज्य का कोई निवासी दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो वह उस राज्य या क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए निर्दिष्ट मूल राज्य में उसे दिए गए विशेष अधिकार या विशेषाधिकार अपने साथ नहीं रखता है। यदि वह अधिकार प्रवासित राज्य में नहीं दिया गया है, तो वह उस पर केवल इसलिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि जिस राज्य से वह प्रवासित हुआ है, उसने वे अधिकार दिए हैं।

प्रतिवादी संख्या 101 दया शंकर वि. हरियाणा राज्य और अन्य ने यूपी राज्य में पिछड़े वर्गों को दिए गए लाभों का आनंद लिया होगा। जब वह वहां रह रही थी, लेकिन हरियाणा राज्य में प्रवास पर, वह पिछड़े वर्गों को दिए गए लाभों का दावा नहीं कर सकती है, जब 'गोस्वामी' जाति को उस राज्य में

पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है, जहां वह स्थानांतरित हुई है। इसलिए, प्रतिवादी नंबर 6 हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है और इस प्रकार, वह निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थी, जो पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था। इसलिए, केवल इसी आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के वकील दीपक सिब्बल

उत्तरदाताओं 1 और 3 से 5 के लिए सूर्यकांत, महाधिवक्ता, हरियाणा, आर.डी. शर्मा, एएजी हरियाणा के साथ नरेंद्र हुडा,

प्रतिवादी नंबर 2 के वकील संजीव कौशिक, प्रतिवादी संख्या 6 के वकील।

निर्णय

न्यायमूर्ति एन.के. सोढी,

(1) इस रिट याचिका में नगर निगम, फ़रीदाबाद (संक्षेप में निगम) के मेयर के रूप में प्रतिवादी 6 के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और उक्त प्रतिवादी इस समुदाय से संबंधित नहीं है। वह वर्ग।

2) याचिकाकर्ता बैरागी जाति से है जिसे हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। उन्होंने मार्च/अप्रैल, 2000 में निगम के लिए वार्ड संख्या 2 से चुनाव लड़ा, जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित था और निर्वाचित घोषित किये गये। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद देविंदर भड़ाना को निगम का मेयर चुना गया। उनके चुनाव को याचिकाकर्ता ने इस अदालत में सिविल रिट याचिका 11831/2000 दायर करके चुनौती दी थी जो अभी भी लंबित है। उस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, देविंदर भड़ाना को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यालय से बाहर कर दिया गया और उनके स्थान पर प्रतिवादी नंबर 6 को निगम का मेयर चुना गया। पार्टियों का यह सामान्य मामला है कि 1 मई, 2000 की अधिसूचना द्वारा, हरियाणा के राज्यपाल ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (इसके बाद इसे कहा जाएगा) कार्य) 2003(2) एलएलआर. पंजाब और हरियाणा 102 हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाएगा) के नियम 71 के उप-नियम (6) के साथ पढ़ें, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि निगम में मेयर का पद निर्वाचित पिछड़े वर्गों के सदस्यों में से भरा जाएगा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 (जिसे इसके बाद नियम कहा जाएगा) के नियम 71 के उप-नियम (6) के साथ पढ़ें, जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि निगम में मेयर का पद निर्वाचित पिछड़े वर्गों के सदस्यों में से भरा जाएगा। अप्रैल, 2000 में चुनाव हुए। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है,

एकमात्र आधार जिस पर हमारे सामने चुनाव को चुनौती दी गई है, वह यह है कि प्रतिवादी संख्या 6 दस्तावेज़ पिछड़े वर्ग से नहीं है। वह जाति से "गोस्वामी" हैं, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा घोषित पिछड़े वर्गों की सूची में नहीं आती हैं और वह "ब्राह्मण" हैं और इसलिए, निगम के मेयर चुने जाने के योग्य नहीं हैं। निगम द्वारा दायर जवाब में, याचिकाकर्ता द्वारा कथित भौतिक तथ्यों का खंडन नहीं किया गया है। निगम की ओर से जो कहा गया है वह यह है कि प्रतिवादी संख्या का चुनाव। 6 निगम के मेयर के रूप में सर्वसम्मति थी और याचिकाकर्ता चुनाव के समय उपस्थित था और उसे तब आपत्ति उठानी चाहिए थी। इस संबंध में। दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता अपने ही द्वारा रोका गया है। रिट याचिका में इस दलील को उठाने से आचरण। यह भी दलील दी गई है कि याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 78 में दिए गए चुनाव याचिका दायर करने के उपाय का उपयोग नहीं किया है और इसलिए, निगम के अनुसार, रिट याचिका खारिज की जा सकती है। प्रत्युत्तर संख्या 6 ने भी रिट याचिका का विरोध किया है और उसने भी रिट याचिका की विचारणीयता पर इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। उसने यह भी आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग से नहीं है और इसलिए, उसकी रिट याचिका उत्तरदायी है। इस आधार पर भी बर्खास्त किया जाए। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 6 पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है, इस पर गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है, हालांकि वह एक प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे वर्ग से संबंधित होने का दावा करती है, जिसकी एक प्रति लिखित बयान के साथ संलग्न की गई है। अनुलग्नक आर- यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है, उत्तरदाताओं 1, 3 और 5 ने कोई उत्तर दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना है।

(3) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और उनका मानना है कि रिट याचिका सफल होने योग्य है। पार्टियों के बीच यह सहमति है कि प्रतिवादी नंबर 6 "गोस्वामी" जाति से है, जिसे हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है। इस मामले में किसी भी उत्तरदाता द्वारा ऐसी कोई घोषणा/अधिसूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। हालांकि, उत्तरदाताओं संख्या 2 और 6 ने बहस के समय उत्तर प्रदेश राज्य में तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा जारी "अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र" की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत की है जो प्रमाणित करती है कि श्रीमती। अनिता गोस्वामी पत्नी 103 दया शंकर वि. हरियाणा राज्य और अन्य (एन.के. सोढ़ी, जे) यूपी राज्य के जिला गाजियाबाद के गांव सीकरी खुर्द के निवासी कृष्ण गोस्वामी (यहां प्रतिवादी नंबर 6) का। "गोसाईं" समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/95-8सीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 में प्रकाशित एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। 13 सितंबर, 1995 को। यूपी राज्य के जिला गाजियाबाद के गांव सीकरी खुर्द के निवासी कृष्ण गोस्वामी (यहां प्रतिवादी नंबर 6) का। "गोसाईं" समुदाय से संबंधित है, जिसे भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/95-8सीसी(सी), दिनांक 10 सितंबर, 1995 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1 में प्रकाशित एक पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। 13 सितंबर, 1995 को। हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 6 को अब हमारे सामने

प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़े वर्ग से संबंधित कहा जा सकता है। भले ही हम प्रमाणपत्र को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करते हैं, प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार गाजियाबाद द्वारा जारी किया गया है और भले ही याचिकाकर्ता यूपी राज्य में पिछड़ा वर्ग है, उसे हरियाणा राज्य में पिछड़ा वर्ग नहीं माना जा सकता क्योंकि हरियाणा राज्य ने "गोस्वामी" जाति को घोषित नहीं किया है। एक पिछड़ा वर्ग, हमें बताया गया कि याचिकाकर्ता मूल रूप से यूपी राज्य का है। लेकिन अब वह फ़रीदाबाद में बस गई हैं जहां से उन्होंने निगम का चुनाव लड़ा। यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है कि जब एक राज्य का कोई निवासी दूसरे राज्य में प्रवास करता है, तो वह उस राज्य या क्षेत्र या उसके हिस्से के लिए निर्दिष्ट मूल राज्य में उसे दिए गए विशेष अधिकार या विशेषाधिकार अपने साथ नहीं रखता है। यदि वह अधिकार प्रवासित राज्य में नहीं दिया गया है तो वह उस पर केवल इसलिए दावा नहीं कर सकता क्योंकि जिस राज्य से वह प्रवासित हुआ है उसने वे अधिकार दिए हैं। प्रतिवादी संख्या 6 ने उत्तर प्रदेश राज्य में पिछड़े वर्गों को दिए गए लाभों का आनंद लिया होगा। जब वह वहां रह रही थी लेकिन हरियाणा राज्य में प्रवास पर, वह पिछड़े वर्गों को दिए गए लाभों का दावा नहीं कर सकती। जब "गोस्वामी" जाति को उस राज्य में पिछड़ा वर्ग घोषित नहीं किया गया है, जहां वह स्थानांतरित हुई है। इस संबंध में मैरी चंद्र शेखर राव बनाम डीन, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और अन्य (1) मामले में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ लिया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी संख्या 6 हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है और इस प्रकार, वह निगम के मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थी, जो कि पद के लिए आरक्षित था। पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार, इसलिए, केवल इसी आधार पर उनका चुनाव रद्द किया जा सकता है।

(4) अब हम उत्तरदाताओं द्वारा ली गई प्रारंभिक आपत्ति से निपट सकते हैं जिसका याचिकाकर्ता को सहारा लेना चाहिए था नियमों के नियम 78 के तहत ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने का वैकल्पिक उपाय। यह सच है कि एक चुनाव याचिका प्रदान की जाती है लेकिन ऐसे उपाय का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। खासकर तब जब प्रतिवादी संख्या 6 का चुनाव हरियाणा के राज्यपाल द्वारा मेयर का पद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने की अधिसूचना के बिल्कुल विपरीत है। प्रतिवादी संख्या 6 को उस पद के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई स्पष्ट रूप से अवैध है और इसलिए, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, हमें इस मामले में हस्तक्षेप करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। वैकल्पिक उपाय समाप्त हो चुका है।

(5) प्रतिवादी संख्या 6 की दलील कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग से है, हमें हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता पिछड़े वर्ग से है, निगम द्वारा विवादित नहीं किया गया है और किसी भी मामले में, उसने पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ वार्ड नंबर 2 से नगरपालिका पार्षद के रूप में चुनाव लड़ा था। यदि वह पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार नहीं है, तो प्रतिवादी

संख्या 6 या कोई अन्य उम्मीदवार कानून के अनुसार उसके चुनाव को चुनौती देने के लिए खुला है। इसके अलावा, यह सवाल कि याचिकाकर्ता पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार है या नहीं, इस रिट याचिका में हमारे सामने मुद्दा नहीं है और इसलिए, हमें इस तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिका इस आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है। हम प्रतिवादियों के इस तर्क में भी कोई दम नहीं पाते हैं कि याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 6 के चुनाव को चुनौती देने से केवल इसलिए रोका गया है क्योंकि वह उस समय उपस्थित था जब वह निगम की मेयर चुनी गई थी। यदि वह पिछड़े वर्ग से नहीं है, तो याचिकाकर्ता के साथ-साथ निगम के किसी भी अन्य सदस्य के लिए उस आधार पर उसके चुनाव को चुनौती देने का अधिकार है। रोक का सवाल ही नहीं उठता।

(6) परिणाम में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और निगम के मेयर के रूप में प्रतिवादी संख्या 6 के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है, जिससे पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी पड़ती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

चाहत  
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी  
अंबाला, हरियाणा